



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 588]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2012/कार्तिक 25, 1934

No. 588]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2012/KARTIKA 25, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2012

सं. 104/2012-सीमा-शुल्क (गै.ट्र.)

सा.का.नि. 831(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 के साथ पठित धारा 141 की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड एतदद्वारा “हैण्डलिंग ऑफ कार्गो इन कस्टम्स एरियाज रेगुलेशन्स, 2009” में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा—

1. (1) इन विनियमों को “हैण्डलिंग ऑफ कार्गो इन कस्टम्स एरियाज (एमेंडमेंट) रेगुलेशन, 2012” कहा जाएगा;
2. (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।
2. “हैण्डलिंग ऑफ कार्गो इन कस्टम्स एरियाज रेगुलेशन्स, 2009” (एतश्मन् पश्चात् जिसे उक्त विनियम से संदर्भित किया गया है) में, विनियम 5 के उप-विनियम (3) के परतुक के स्थान पर निम्नलिखित परतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—
“बशर्ते कि बैंक गारण्टी या कैश जमा करने की शर्त उन पत्तनों पर जो कि “मेजर पोर्ट्स एक्ट, 1962” (1963 का 38) के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या उनके प्रतिस्थानों पर या सीमा-शुल्क कार्गो सेवा प्रदाता जो कि प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक कार्यक्रम के अंतर्गत प्राधिकृत हैं पर लागू नहीं होती हैं।”
3. उक्त विनियमों के विनियम 10 के उप-विनियम (2) में निम्नलिखित परतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—
“बशर्ते और भी कि प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक कार्यक्रम के अंतर्गत प्राधिकृत किए गए सीमा-शुल्क कार्गो सेवा प्रदाता के मामले में उप-विनियम (1) के अंतर्गत दिए गए अनुमोदन को एक समय में आगे 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।”

[फा. सं. 450/55/2008-सीमा-शुल्क-IV]

एस. सी. गंगर, अवर सचिव

पाद टिप्पणी :—प्रधान विनियम को सा.का.नि. 174(अ), दिनांक 17 मार्च, 2009 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार सा.का.नि. 370(अ), दिनांक 16 मई, 2012 के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2012

No. 104/2012-Customs (N.T.)

G.S.R. 831(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 141, read with Section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Handling of Cargo in Customs Areas Regulations, 2009, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Handling of Cargo in Customs Areas (Amendment) Regulation, 2012.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Handling of Cargo in Customs Areas Regulations, 2009 (herein after referred to as the said regulations), for the proviso to sub-regulation (3) of the regulation 5, the following proviso shall be substituted, namely :—
“Provided that the condition of furnishing of bank guarantee or cash deposit shall not be applicable to ports notified under the Major Ports Act, 1962 (38 of 1963) or to the Central Government or State Governments or their undertakings or to the Customs Cargo Service provider authorised under Authorised Economic Operator Programme.”.
3. In sub-regulation (2) of regulation 10 of the said regulations, the following proviso shall be inserted, namely :—
“Provided further that in case of Customs Cargo Service provider authorised under Authorised Economic Operator Programme, the approval granted under sub-regulation (1) may be extended for a further period of ten years at a time.”.

[F. No. 450/55/2008-Cus.-IV]

S. C. GANGER, Under Secy.

Foot Note :—The principal regulations were published *vide* number G.S.R. 174(E), dated the 17th March, 2009 and last amended *vide* number G.S.R. 370(E), dated the 16th May, 2012.